

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-2

संख्या-1226/IV(2)-श0वि0-15-10(सा0)/14

देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप।

नगर निगमों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से उनकी स्वयं की आय में वृद्धि हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं, किन्तु नगर निगमों के सार्थक प्रयास/उदासीनता के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

नगर निगमों में कार्मिकों के वेतन, पेंशन आदि की देनदारियाँ लम्बित हैं, साथ ही अन्य अवस्थापना सुविधा सम्बन्धी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आय में वृद्धि के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त सम्पत्ति कर निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) व्यवसायिक भवनों में वर्ष- 2014 के सर्किल रेट के आधार पर अधिक कर निर्धारण के कारण उत्पन्न असन्तोष को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2012-14 के सर्किल रेट के आधार पर कर निर्धारण किया जाय, ताकि कर वसूली में आसानी हो सके।

(2) जो क्षेत्र नगर निगम गठन के बाद सम्मिलित किये गये हैं, तथा जहाँ विकास नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में आवासीय भवनों के स्वकर निर्धारण हेतु कारपेट एरिया के अनुसार आंकलित दरों में अपेक्षाकृत आंशिक रियायत प्रदान करने पर विचार किया जाय।

(3) नगर निगम अधिनियम- 1959 एवं नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली- 2000 के अनुसार आवासीय भवनों पर करों का निर्धारण स्वकर प्रणाली के आधार पर किया जाय। वर्तमान तक जिन नगर निगमों यह प्रक्रिया लागू नहीं की गयी है, उसे तत्काल लागू कर प्राविधानों के तहत कर निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए, ताकि आय में वृद्धि हो सके।

(4) नगर निगम अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यकारिणी समिति को मूल्यांकन तथा निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई कर आपत्तियों का अनुसंधान और निपटारा करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु यदि समान निर्धारित रीति से आरोपित करों को मनमाने तरीके से कम किया जाता है तो नगर आयुक्तों का यह दायित्व होगा कि ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कर शासन को उपलब्ध कराई जाय।

कमश:-2/-



(5) समस्त नगर निगमों द्वारा शतप्रतिशत कर निर्धारण/वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि उनकी समयान्तर्गत देनदारियाँ पूर्ण हो सकें।

(6) नगर निगम में लागू उपविधियों की समीक्षा कर उनमें आवश्यक सुधार लाने एवं करों/शुल्क में वर्तमान स्थिति के अनुसार वृद्धि किये जाने की कार्यवाही भी अमल में लायी जाय।

(7) नगर निगम सीमान्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को भी देख लिया जाय जो अत्यधिक विकसित हों, जहां नवीन करारोपण की आवश्यकता हो, ताकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

(8) सम्पत्ति कर निर्धारण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय।

(9) समस्त नगर निगम प्रत्येक दशा में 06 माह के भीतर नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार कर निर्धारण का कार्य पूर्ण करें।

(10) उक्त निर्णयों के अनुपालन का दायित्व नगर आयुक्तों का होगा।

(11) इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी।

उक्तानुसार निर्णयों का अनुपालन करते हुए अत्यन्त तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(डी०एस०/गर्ब्याल)  
सचिव।

संख्या-1226/IV(2)-श०वि०-15-10(सा०)/14, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।

4- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे शहरी विकास विभाग की वेबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

5- निजी सचिव, मा० मंत्री, शहरी विकास विभाग को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)  
उप सचिव।